

# यूपी के ग्रोथ का इंजन बने एक्सप्रेस-वे



दिग्विजय सिंह

कानपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका यह सपना साकार भी होता दिख रहा है, क्योंकि सूबे में बनाए गए एक्सप्रेस-वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। अभी जो एक्सप्रेस-वे बने हैं, उनकी वजह से यात्रा का समय कम हुआ है। कनेक्टिविटी बेहतर होने से रियल एस्टेट के लिए नए अवसर खुले हैं। अभी और एक्सप्रेस-वे बनने जो रहे हैं, जो औद्योगिक विकास को गति देंगे। पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा, रियल एस्टेट के क्षेत्र में निवेश होगा। साथ ही मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इससे उत्तर प्रदेश की जीडीपी मजबूत होगी।

प्रदेश में नौ नए एक्सप्रेस-वे बनाने की तैयारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। फिलहाल नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे, आगरा-नोएडा यमुना एक्सप्रेस-वे पर वाहन दौड़ रहे हैं। इनका निर्माण राज्य सरकार ने कराया है। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे भी बन गया है। जल्द ही लखनऊ लिंक एक्सप्रेस-वे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे, जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे, विन्ध्य एक्सप्रेस-वे, मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेस-वे, चित्रकूट-रीवा लिंक एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे व गोरखपुर-शामली एक्सप्रेस-वे बनने जा रहा है। इन सभी की लंबाई 2096 किलोमीटर होगी। इनके निर्माण पर करीब 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होने होने हैं।

इनमें से गोरखपुर से शामली एक्सप्रेस-वे व गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे का निर्माण केंद्र सरकार कराएगी और शेष का निर्माण राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा। इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। ये सर्वाधिक

एक्सप्रेस-वे वाले उत्तर प्रदेश में जब प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे धरातल पर उतरेंगे, तो यहां की तस्वीर कुछ और ही होगी। कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में आने वाले उत्तर प्रदेश में आज तेजी से निवेश हो रहा है। खासकर एक्सप्रेस-वे के किनारे। नई टाउनशिप बन रही हैं, जो लोगों के आवास की जरूरतें पूरी कर रही हैं, तो वेयरहाउस भी खूब बन रहे हैं। औद्योगिक विकास को भी गति मिली है।

बढ़ते निवेश से रोजगार के अवसर तो बढ़ ही रहे हैं। यहां के युवा, जो दूसरे महानगरों में नौकरी के लिए जा रहे हैं, उनका पलायन भी कुछ हद तक रुका है। एक्सप्रेस-वे पर बनने वाली हवाई पट्टी भी हमें सामरिक बढ़त दिला रही है। यही वजह है कि जो भी एक्सप्रेस-वे बनेंगे, सब पर हवाई पट्टी होगी, ताकि युद्ध के समय उनका उपयोग हो सकेगा। अकेल गंगा एक्सप्रेस-वे से उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बूस्ट मिलने की बड़ी उम्मीद है। इस एक्सप्रेस-वे से ही जीडीपी में एक लाख करोड़ रुपये के इजाफे की उम्मीद है। इसके साथ ही इस एक्सप्रेस-वे से लॉजिस्टिक्स की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। इस बात की उम्मीद है कि इससे प्रत्येक साल लॉजिस्टिक्स में 25 हजार से 30 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी।

गंगा एक्सप्रेस-वे के कई जगहों पर टूटने और बारिश का पानी भरने से थोड़ी किरकरी तो हुई है, पर इसका डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो कभी यहां औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए बड़े निवेशकों को काफी समझना पड़ता था, लेकिन आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के बनने के बाद जैसे ही माल ढुलाई आसान हुई कई मल्टी नेशनल कंपनियों ने भी वहां न सिर्फ निवेश किया है, बल्कि अब वे अपनी इकाइयों के विस्तार की भी सोच रही हैं। सूबे में दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, भंडार गृह और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में खूब निवेश बढ़ा है, तो फार्मा, कपड़ा और आईटी सेक्टर भी बूम कर रहा है।

निवेश के लिए भूमि की बढ़ती मांग ने ही सरकार के हौसले को बढ़ाया है यही वजह है कि सरकार का पूरा ध्यान एक के बाद एक एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर है। इसके साथ ही बड़े शहरों में आउटर रिंग रोड की स्थापना का कदम भी बढ़ा ही सराहनीय है। आउटर रिंग रोड की परियोजनाएं वैसे तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की हैं, पर राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा समन्वय, समय से दी जा रही एनओसी और वित्तीय सहभागिता ने इस परियोजना को गति दी है। एक्सप्रेस बनना ही काफी नहीं था, क्योंकि वाहन आकर शहरों से गुजरने वाले मुख्य मार्गों पर जाम में फंसते हैं, पर रिंग रोड बनने से उन्हें शहर के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं होगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहे जाने वाले कानपुर में जाम की वजह से ही कोई बड़ा निवेशक निवेश को तैयार नहीं था, लेकिन रिंग रोड का निर्माण शुरू होते ही बड़े उद्योगपतियों ने यहां निवेश के लिए भूखंड आवंटन कराना शुरू कर दिया। यहां तक कि अडानी ग्रुप ने कानपुर स्थित अपनी डिफेंस इकाई के विस्तार के लिए दो सौ हेक्टेयर से अधिक भूमि भी मांग ली है। उसका अधिग्रहण भी शुरू हो गया है। गंगा एक्सप्रेस-वे किनारे 12 जिलों में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 46,660 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। अब तक 987 से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जो यह बताने के लिए काफी है कि एक्सप्रेस-वे यूपी के ग्रोथ का इंजन बनने जा रहे हैं।

राजनीति की समझ रखने वालों का मानना है कि एक्सप्रेस-वे ग्रोथ का इंजन तो बनेंगे ही, प्रदेश सरकार की पुनः सत्ता में वापसी के लिए मजबूत आधार भी तैयार करेंगे। कुछ लोग मानते हैं कि एक्सप्रेस-वे के टूटने या पानी भरने से सरकार की छवि को धक्का लगा है फिर भी यूपी के विकास में ये एक्सप्रेस-वे अहम भूमिका अदा कर रहे हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

एक्सप्रेस-वे की वजह से यात्रा का समय कम हुआ है। कनेक्टिविटी बेहतर होने से रियल एस्टेट के लिए नए अवसर खुले हैं। अभी और एक्सप्रेस-वे बनने जा रहे हैं, जो औद्योगिक विकास को गति देंगे।